



संक्षिप्त

समाचार

केरल के पूर्व सीएम के खिलाफ होगी एफआईआर

पिनराई विजयन और उनकी बेटी पर भ्रष्टाचार का लगा है आरोप

तिरुअनंतपुरम (एजेंसी)। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार केस में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस केस में पिनराई विजयन और उनकी बेटी टी वीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मामला कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड और वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है। कोर्ट में याचिका देकर इस मामले में जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने यह फैसला दिया। दरअसल, इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही थी और उसने केरल पुलिस के साथ भी इसकी जांचकारी साझा की थी। इसके बाद भी राज्य पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय विशेष जांच टीम बनाई थी। ईडी और राज्य सरकार की दलीलें-हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग का समर्थन किया। ईडी के वकील जयशंकर नायर ने कहा कि जांच के दौरान कई ऐसे लेन-देन सामने आए हैं, जिनकी जांच राज्य पुलिस या किसी सक्षम एजेंसी से कराना जरूरी है। राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल जाजू बाबू ने याचिका की सुनवाई योग्य होने पर शुरुआती आपत्ति जताई।

दिवशा डेथ केस में सास गिरिबाला की बड़ी मुसीबतें

दहेज एवट की धाराएं हटीं, लेकिन जमानत पर संशय

जबलपुर (एजेंसी)। मॉडल टिवसा शर्मा की मौत के मामले में जेल में निरुद्ध भोपाल की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं को विलोपित कर पेश की गई संशोधित याचिका स्वीकार कर ली। सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से बताया गया कि मामले में जुटाए गए तकनीकी साक्ष्यों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच एजेंसी मामले की पड़ताल कर रही है और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कानून के अनुसार संबंधित न्यायालय में आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका जिला न्यायालय से खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। पिछली सुनवाई में अदालत को बताया गया था कि दहेज की मांग से जुड़े साक्ष्य नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने मामले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं हटा दी हैं। इसके बाद एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को दहेज एवट की धाराएं हटाकर संशोधित याचिका पेश करने के निर्देश दिए थे।

अब पीएम मोदी के नाम से जाना जाएगा नोएडा एयरपोर्ट

अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण, बिना परीक्षा जॉइनिंग मिलेगी योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, एयरपोर्ट में पार्किंग की सुविधा रहेगी

नोएडा (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया है। नोएडा जेवर एयरपोर्ट का नाम अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शुक्रवार को कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी क्षमता एक वर्ष में लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है। यह एयरपोर्ट 1300 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में बनने वाला यह दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ कम करने में मदद करेगा। नोएडा एयरपोर्ट पर ग्रांड ट्रॉसपोर्टेशन सेंटर विकसित किया गया है।

जेएनयू ने प्रोफेसर बिमोल अकोइजाम को किया बर्खास्त

कांग्रेस सांसद 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए मणिपुर हिंसा के दौरान राजनीति में आए थे, बीसी से शिकायत

नई दिल्ली (एजेंसी)। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर और इनर मणिपुर से कांग्रेस लोकसभा सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को बर्खास्त कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने उन्हें 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। बर्खास्तगी तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी की इंटरनल कमिटी की जांच के निष्कर्षों के आधार पर की गई। बीसी ने बिमोल अकोइजाम के खिलाफ बड़ी सजा की सिफारिश की थी। 2023 में मणिपुर हिंसा के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इनर मणिपुर सीट से लड़े और भाजपा उम्मीदवार को 1 लाख से अधिक वोटों से हराकर सांसद चुने गए।

मुंबई में 18 दिसंबर से होगी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस

उद्घाटन सत्र को मोहन भागवत करेंगे संबोधित

मुंबई (एजेंसी)। दुनियाभर के हिंदू नेतृत्व, विचारकों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का वैश्विक समागम वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस (डब्ल्यूएचसी) 2026 इस बार मुंबई में होगा। तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 दिसंबर तक बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत संबोधित करेंगे। आयोजकों के अनुसार, सम्मेलन में 60 से अधिक देशों के चार हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें हिंदू नेता, विचारक, उद्यमी, शिक्षाविद, मीडिया प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर एक मंच पर जुटेंगे। तीन दिनों में 45 से अधिक सत्र होंगे और 150 से अधिक वक्ता अपने विचार रखेंगे। सम्मेलन अर्थव्यवस्था, शिक्षा, अकादमिक जगत, मीडिया और राजनीति जैसे क्षेत्रों में हिंदू समाज की भूमिका को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सम्मेलन में भाषा, समाज और धर्म विषयों पर विशेष सत्र होंगे। सम्मेलन के साथ पहली बार वर्ल्ड हिंदू एक्सपो भी आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य व्यापार-वाणिज्य और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

मक्खी मारने के लिए हथौड़ा न चलाएं

सीजेपी के प्रदर्शन से पहले सख्ती पर चीफ जस्टिस की टिप्पणी सरकार को लगाई फटकार, दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशन बंद, ट्रेनें रद्द

सुप्रीम कोर्ट बोला- मेट्रो पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकते

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेट्रो की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। अधिकारियों को मेट्रो और अन्य ट्रेनों की आवाजाही इस तरह नियंत्रित करने पर विचार करना होगा कि आम लोगों को परेशानी न हो। इस फैसले की जानकारी दी जाए और शहर में यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी से बचाने के लिए एडवाइजरी अखबारों और वेबसाइटों पर भी प्रकाशित की जाए। इस पर तुषार मेहता ने कहा, कोर्ट ने एक उदाहरण के तौर पर यह बात कही है। यह इस तरह से रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए कि भारत के चीफ जस्टिस ने कहा है कि सरकार मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल कर रही है।

भारतवंशी नावी पिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार

फिर खाली हाथ रह गए डोनाल्ड ट्रंप, लगा बड़ा झटका

ओस्लो (एजेंसी)। मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अमिट छाप छोड़ने वाली भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी ज्यूरिस्ट नवेनेथम 'नावी' पिल्ले को प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के हाथ फिर से खाली रह गये हैं और उन्हें इस साल भी नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया है। 88 वर्ष की नावी पिल्ले का जन्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक भारतीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके दादा तमिलनाडु से दक्षिण अफ्रीका जाकर बसे थे। विपरीत परिस्थितियों और रंगभेद के दौर में पढ़ाई पूरी कर वह दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू करने वाली पहली गैर-श्वेत महिला बनी थीं। मानवाधिकारों की लड़ाई में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा है। रंगभेद के क्रूर दौर के दौरान उन्होंने नेल्सन मंडेला के राजनैतिक बंदियों और अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुकदमों की पैरवी की और जेलों में प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई। वह 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त रह चुकी हैं। वह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जज और रवांडा के लिए बने ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष भी रही हैं।

गुजरात के कच्छ में भीषण सड़क हादसा

सात मजदूरों की हो गई मौत, 20 से ज्यादा हैं घायल

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात के कच्छ स्थित खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के अंदर मार्ग पर तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। श्रमिकों को ले जा रही एक बोलेरो और अन्य वाहन बल्कर के बीच आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में 7 मजदूरों की मौतें पर ही मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तीव्र थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें कई श्रमिक फंस गए। गंभीर हादसे की सूचना मिलते ही पश्चिम कच्छ पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और क्रैन की मदद से फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला, जिससे समय रहते कई जिंदगियों को बचाया जा सका। सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए खावड़ा से भुज भेजा जा रहा है। खावड़ा आरई पार्क क्षेत्र में हुए इस तरह के पहले बड़े हादसे को लेकर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। कच्छ कलेक्टर खुद मामले को देख रहे हैं।

उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी की बल्ले-बल्ले

बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर में मिली बंपर जीत असम में बीजेपी और पुडुचेरी में एनडीए ने मारी बाजी

नई दिल्ली (एजेंसी)। चार राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव की कार्डटिंग संपन्न हो गई है। बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा की बंपर जीत हुई है। नंदीग्राम में भाजपा की हसीरानी रथ को 1 लाख से ज्यादा वोट की जीत मिली है। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में सीएम शुभेंद्रु अधिकारी नंदीग्राम में 9 हजार वोट से जीते थे। तमिलनाडु की दोनों मद्रुतकम और धारापुरम सीटों पर सीएम विजय की पार्टी टीवीके ने बड़ी जीत हासिल की है। पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट पर एनडीए समर्थित उम्मीदवार अशोक आनंद जीत गए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है।

बीजेपी उम्मीदवार हसीरानी रथ को मिली बड़ी जीत- नंदीग्राम उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार हसीरानी रथ को एक लाख 20 हजार से अधिक वोटों से जीत मिली है। उन्होंने अपनी जीत में सीएम सुवेंदु अधिकारी की तरफों को प्रशिक्षित किया है। सुवेंदु अधिकारी को पिछले चुनाव में महज नौ हजार वोटों से जीत मिली थी। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार उपचुनाव हुए हैं। चुनाव में बीजेपी की सुनामी देखने को मिली है।

मौत के कारणों का पता लगाएगी पुलिस, देर रात हुआ अंतिम संस्कार

मुंबई (एजेंसी)। गोवा पुलिस ने अभिनेता नाना पाटेकर के निधन मामले में मेडिको-लीगल 'अप्राकृतिक मौत' का केस दर्ज किया है। पुलिस मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिवार के बयानों की जांच करेगी। न्यूज एजेंसी के अनुसार, गोवा पुलिस ने बीएनएस की धारा 194 के तहत केस दर्ज किया है। पीएसआई नितिन नाइक इसकी जांच कर रहे हैं। पणजी में दर्ज केस के मुताबिक, नाना पाटेकर को गुरुवार सुबह गोवा के डोना पाउला स्थित ओशन पार्क से मणिपाल अस्पताल, बांबोलिम लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देर रात पुणे के फार्म हाउस में शव का अंतिम संस्कार किया गया।

अस्पताल ने कहा- मृत लाया गया

मणिपाल अस्पताल के ऑनकोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर शेखर सालकर ने बताया कि नाना पाटेकर को अस्पताल में मृत अवस्था में ही लाया गया था। इसी वजह से पुलिस केस दर्ज कराना पड़ा और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज के मुल्हाष भेजा गया। डॉक्टर के मुताबिक प्राथमिक तौर पर यह कार्डियक अरेस्ट का मामला लगता है।

वीजा लेकर अमेरिका में काम करने वाले बंधुआ मजदूर: वेंस

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एच-1बी वीजा पर अमेरिका में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को 'बंधुआ मजदूर' बताया है। भारत ने वेंस के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में प्रवासियों की अहम भूमिका रही है। भारत ने यह भी कहा कि भारतीय पेशेवर अमेरिका की अर्थव्यवस्था, नई तकनीक, रिसर्च और रोजगार बढ़ाने में अहम योगदान देते हैं। इससे दोनों देशों को फायदा होता है। अमेरिका में एच-1बी वीजा पाने वालों में 71 फीसदी भारतीय हैं। वेंस ने माइक्रोसॉफ्ट पर वीजा व्यवस्था का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया।

8 आईटी कंपनियों के ग्रीन कार्ड प्रोग्राम पर रोक- अमेरिकी सरकार ने 8 बड़ी आईटी कंपनियों को ग्रीन कार्ड से जुड़ी आईटी कंपनियों को प्रकिया से सस्पेंड कर दिया है। इनमें भारत की इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, टीसीएस और कॉग्निजेंट के साथ माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और कैपजेमिनी शामिल हैं। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देकर अमेरिकी लोगों के रोजगार के अवसर कम कर रही हैं।

संक्षिप्त समाचार

छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : रेखा गुप्ता

अनप्लग इंडिया नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में अंधेरी जगहें, लाइटिंग की कमी, टूटे फूटपथ और कचरे की समस्या के जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने देर रात दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस पहुंचीं। यहां उन्होंने आर्ट्स फैकल्टी के बाहर छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी सुरक्षा, परिवहन, हॉस्टल और कॉलेज से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं से बातचीत करते हुए पूछा कि रात में आने-जाने में कोई परेशानी या असुरक्षा तो महसूस नहीं होती और कॉलेज से जुड़ी कोई समस्या हो तो वह भी उन्हें बताएं। उन्होंने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि उनकी हर उचित समस्या के समाधान के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कैंपस में निरीक्षण करते हुए कई डार्क स्पॉट देखे और अधिकारियों से मौके पर ही उनकी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सड़क पर पर्याप्त रोशनी होने के बावजूद कैंपस के अंदर कई स्थानों पर अंधेरा दिखाई दे रहा है, जबकि यहां छात्राओं और विद्यार्थियों की लगातार आवाजाही रहती है।

निगमायुक्त ने मोलड़बंद क्षेत्र का किया निरीक्षण, जनसमस्याओं के त्वरित एवं स्थायी समाधान के लिए निर्देश

अनप्लग इंडिया नई दिल्ली। निगमायुक्त संजीव खिरवार ने मोलड़बंद क्षेत्र का निरीक्षण कर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, जलभराव, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, अतिक्रमण, कूड़ा प्रबंधन तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मोलड़बंद गांव स्थित एमसीडी प्राथमिक विद्यालय की स्थिति का विशेष रूप से जायजा लिया गया। विद्यालय के कुछ कमरों में मरम्मत की आवश्यकता रहे देखते हुए निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को क्षतिग्रस्त कमरों की आवश्यक मरम्मत का कार्य आगामी सोमवार तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरम्मत कार्य पूरा होने तक विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे और बच्चों को अस्थायी रूप से सुरक्षित वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कर उनकी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखी जाए। विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए पार्क के लिए भी निर्देश दिया। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मोलड़बंद एक्सटेंशन स्थित एमसीडी प्राथमिक विद्यालय के समीप पोटा केबिन परिसर में एमसीडी डिस्पेंसरी शुरू करने की संभावना पर भी चर्चा की गई।

दिल्ली के प्रेम नगर में तालाब में मिला 7 साल के मासूम का शव, दूसरे भाई की तलाश जारी

अनप्लग इंडिया नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक पुराने तालाब में सात वर्षीय मासूम बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे सगे भाई थे और गुप्तावर दोपहर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक, प्रेम नगर इलाके में स्थित पुराने तालाब में एक बच्चे का शव पानी में तैरता दिखाई दिया। राहगीर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से शव को गहरे पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है। परिजनों ने दोनों बच्चों की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में पोस्टर भी लगाए थे। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, दूसरे बच्चे का पता लगाने के लिए तालाब में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, तालाब काफी पुराना है और यहां लंबे समय से पानी भरा रहता है, यहां लोग मछली पकड़ने आते हैं और कुछ बच्चे नहाने के लिए भी तालाब में उतरते हैं।

दिल्ली पुलिस ने ‘इंडिया’ ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में कश्मीरी युवक से मारपीट मामले में दर्ज की एफआईआर

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने ‘इंडिया’ ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन के दौरान हाल ही में कश्मीरी युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज की है। कश्मीरी युवक ने मारपीट के बाद पुलिस में शिकायत दी थी। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कश्मीरी युवक युवक की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने ‘प्लांट मंडला रंगोली’ का किया उद्घाटन

अनप्लग इंडिया नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर्नाट प्लस स्थित सेंट्रल पार्क के एम्सथिएटर में ‘प्लांट मंडला रंगोली’ का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्लांट मंडला का अवलोकन किया और उपस्थित लोगों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मंडला रंगोली भारतीय कला और संस्कृति की सुंदर एवं समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। इस विशेष कार्यक्रम में कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, विधायक अशोक गोयल उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंडला में लगाया गया प्रत्येक पौधा केवल कलात्मक रचना का हिस्सा नहीं, बल्कि पौधे लगाने, उनकी रक्षा और पोषण करने तथा दिल्ली के वन एवं शहरी हरित क्षेत्रों को संरक्षित और विकसित



बेहतर जीवन-स्तर के निर्माण में योगदान देता है। उन्होंने कहा कि इस ‘प्लांट मंडला रंगोली’ के माध्यम से ‘विकसित भारत 2047’ और ‘विकसित दिल्ली’ के संकल्प को भी एक साथ अभिव्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों के सामने रखे गए ‘हम करके रहेंगे’ के संकल्प

महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हेल्थ, यूथ और डिफेंस की विशक्ति एक साथ मिलकर एक राष्ट्रीय मिशन को जन्मभगीदारी का व्यापक स्वरूप दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोश टीमों के माध्यम से युवा वॉलंटियर्स, एनसीसी कैडेट्स, जनप्रतिनिधि और

57वीं जीएसटी परिषद बैठक में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता

बोली- सुधारों से बनेगी पारदर्शी और कारोबार अनुकूल कर व्यवस्था सरल एवं करदाता-अनुकूल बनेगी।

अनप्लग इंडिया नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में भागीदारी की। मुख्यमंत्री ने जीएसटी परिषद द्वारा प्रस्तावित विभिन्न सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य देश में एक ऐसी कर व्यवस्था विकसित करना है, जो पारदर्शी, कुशल, उत्तरदायी और कारोबार के अनुकूल हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में ‘सबका साथ, सबका विकास,



अधिक सुविधाजनक बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि रिफंड की प्रक्रिया स्वचालित होने से कारोबारियों को उनका पैसा समय पर मिल सकेगा और इससे निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी।

युवा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाएं : दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता

‘शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने ऐतिहासिक दिल्ली विधानसभा परिसर का निर्देशित भ्रमण किया’

अनप्लग इंडिया नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि युवाओं को कभी भी अपने जोश पर होश हावी नहीं होने देना चाहिए। आपकी ऊर्जा, विचार और आकांक्षाएं तभी सार्थक हैं, जब उन्हें जागरूकता, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना का मार्गदर्शन मिले। यह बात विजेंद्र गुप्ता

भाजपा महिला मोर्चा का महिला पुलिस से कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन

अनप्लग इंडिया नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के पास रौप प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली भाजपा महामंत्री योगिता सिंह ने किया।

इस दौरान महिला मोर्चा प्रभारी आरती मेहरा, अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष सारिका जैन और विधायक शिखा रॉय समेत बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। प्रदर्शनकारी दोनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित आंध्रा भवन रेड लाइट पर एकत्र हुई और नारेबाजी करते हुए कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ीं। पुलिस ने हिन्दी भवन के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद महिला कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गईं। कुछ देर बाद पुलिस ने चेतावनी देकर प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने दिया।

इस दौरान भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। दिल्ली भाजपा महामंत्री योगिता सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन महिला पुलिस कर्मियों का अपमान और उनके साथ दुर्व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा व्यवहार

सकता। विकसित दिल्ली वह होगी, जहां विकास के साथ प्रकृति, स्वच्छ हवा, हरित क्षेत्र और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को भी समान महत्व मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा से राष्ट्रसेवा की यात्रा के अवसर पर दिल्ली की जनता को शुभकामनाएं देते हुए वह यह संकल्प दोहराती हैं कि दिल्ली विकसित भारत की इस व्यापक यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि ‘प्लांट मंडला रंगोली’ भारतीय कला, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का सुंदर संगम है। जीवित पौधों से तैयार यह अनूठी रचना दिल्ली को हरित और सुंदर बनाने के साथ-साथ प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संदेश भी देती है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप दिल्ली की विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर आगे बढ़ रही है।

अधिकारी मिलकर जनता के बीच जाएंगे और टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ इसके उन्मूलन के प्रयासों के प्रबलत करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और संकल्प को इस मिशन से जोड़कर टीबी के खिलाफ लड़ाई को जन-जन

वहीं स्वचालित रूप से पंजीकरण रह होने की व्यवस्था से कारोबार बंद करने वाले करदाताओं को



अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है। इससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए भी पंजीकरण अधिक सुगम होगा।

तर्कसंगत बनाने जैसे कदम देश में कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे। इन सुधारों से देश में कारोबार करना आसान होगा और जीएसटी व्यवस्था अधिक सरल एवं करदाता-अनुकूल बनेगी।

क्षेत्रों और शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से आए छात्रों को विधानसभा अध्यक्ष



के साथ सीधे संवाद करने तथा कक्षा और पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर विधायिका के कामकाज को समझने का अवसर प्रदान किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने

कहा कि युवाओं में अपार ऊर्जा, जिज्ञासा और आकांक्षाएं होती हैं,



लेकिन इनका साथ जागरूकता, धैर्य और विवेक से होना आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहने, सोच-समझकर निर्णय लेने और अपनी क्षमताओं का

दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की अध्यक्ष पश्चिमी जोन में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचीं

अनप्लग इंडिया नई दिल्ली। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, जीएनसीटीडी की अध्यक्ष सुनीता कांगड़ा ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पश्चिमी जोन का दौरा कर सफाई व्यवस्था और सफाई कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सफाई विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया और कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित विषयों पर अधिकारियों एवं यूनियन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता पश्चिमी जोन के अध्यक्ष हरीश ओबेरॉय और उपायुक्त कर्नल विनोद अत्री ने की। बैठक में सहायक आयुक्त, सफाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न सफाई कर्मचारी यूनियनों के

प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण, लंबित बकाया, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य सेवा संबंधी मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। यूनियन प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को आयोग के समक्ष रखा, जिन पर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

सुनीता कांगड़ा ने पश्चिमी जोन में सफाई व्यवस्था में सुधार और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जोन में अपनाई जा रही बेहतर कार्यप्रणालियों और विभिन्न पहलों को अन्य जोन के साथ साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सफल मॉडलों को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके।

रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने आसपास हो रहे बदलावों का केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनमें ऐसी समझ और जिम्मेदारी की भावना विकसित होनी चाहिए, जो उन्हें राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान देने के योग्य बनाए। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने ऐतिहासिक दिल्ली विधानसभा परिसर का निर्देशित भ्रमण किया और इसकी विशिष्ट स्थापत्य शैली तथा भारत के संसदीय इतिहास में इसके महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। डॉक्यूमेंट्री और प्रस्तुतियों के माध्यम से छात्रों को इस भवन के केंद्रीय विधान सभा से जुड़े इतिहास

तथा इससे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों से परिचित कराया गया। छात्रों ने मुख्य विधानसभा सदन का भी दौरा किया, जहां उन्हें उस स्थान को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने का अवसर मिला, जहां विधायी बहसों और विधानसभा की कार्यवाही संचालित होती हैं। उन्हें विधानसभा की संसदीय विरासत तथा विधानसभा की स्मारिका कॉफी टेबल बुक ‘एक शताब्दी यात्रा’ से भी परिचित कराया गया, जिसमें इस संस्था की ऐतिहासिक यात्रा और विरासत को संकलित किया गया है। इस दौरे ने छात्रों को भारत की विधायी संस्थाओं के इतिहास को

एमसीडी का दिल्लीभर में बड़ा प्रवर्तन अभियान

21 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई

अनप्लग इंडिया नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अनधिकृत निर्माण, खतरनाक भवनों और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ दिल्लीभर में अपना प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। निगम ने सप्ती 12 जोन में कार्रवाई करते हुए कुल 21 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। इसके अलावा 4 संपत्तियों को सील किया गया और 4 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। एमसीडी के अनुसार, निगम के सभी जोन में भवन निर्माण संबंधी नियमों के अनुपालन और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। चिन्हित उल्लंघनों के खिलाफ दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी), भवन उपनियमों और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।

गुरुवार की कार्रवाई के दौरान रघुबीर नगर, संत नगर, गुरुमंड़ी राजपुरा और कल्याण विहार समेत

दिल्ली के विभिन्न इलाकों में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। निगम ने स्पष्ट किया कि उसके क्षेत्राधिकार में किसी भी तरह के अनधिकृत निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे एक दिन पहले भी एमसीडी ने अपने प्रवर्तन अभियान के तहत 27



ध्वस्तीकरण कार्रवाइयों की थीं और 3 संपत्तियों को सील किया था। लगातार हो रही कार्रवाई से निगम ने संकेत दिया है कि भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा। एमसीडी ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में कड़ी निगरानी रखने और

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निर्धारित प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निगम के मुताबिक, अनधिकृत निर्माण, खतरनाक इमारतों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाले अन्य उल्लंघनों के खिलाफ सप्ती 12 जोन में अभियान लगातार जारी रहेगा।

दिल्ली में 11 अक्टूबर को सभी पोलिंग बूथों पर लगेंगे कैप

5 लाख से ज्यादा नो- मेपिंग व तार्किक विसंगति मामलों का हुआ निपटारा

अनप्लग इंडिया नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत छूटे मतदाताओं को जुड़ने के लिए दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशनों पर 9 और 11 अक्टूबर को विशेष कैप आयोजित किए है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए 7 और 8 अक्टूबर को विशेष कैप लग रहे हैं।

इससे पहले 29 और 30 सितंबर को भी ऐसे कैप लगे थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक नोट करते हुए बताया कि अब तक 15,30,408 नो- मेपिंग और तार्किक विसंगति मामलों का दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करके निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि बीएलओ खुद घर जाकर नोटित वाले मतदाताओं से



के साथ जोश टीमें देशभर में काम करेंगी और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगी। उन्होंने सभी युवाओं से इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनकर टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने और समाज को इस बीमारी से मुक्त करने के प्रयासों में योगदान देने

का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए ‘हम करके रहेंगे’ के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि यह विश्वास हमें हर चुनौती का सामना करने की ऊर्जा देता है। कुछ भी असंभव नहीं है और हर असंभव के भीतर संभव की संभावना

छिपी होती है। इसी विश्वास के साथ देश को टीबी-मुक्त बनाने और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। विकसित भारत का संकल्प तभी पूर्ण होगा, जब भारत स्वस्थ और समृद्ध होगा।

हेल्थ, यूथ और डिफेंस की त्रिशक्ति मिलकर टीबी-मुक्त भारत के संकल्प को करेगी साकार : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में जॉइंट स्क्वाड फोर हेल्थ (जोश) टीमों के शुभाभिन कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने टीबी-मुक्त भारत के राष्ट्रीय मिशन में युवाओं की सक्रिय भूमिका को

महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हेल्थ, यूथ और डिफेंस की त्रिशक्ति एक साथ मिलकर एक राष्ट्रीय मिशन को जन्मभगीदारी का व्यापक स्वरूप दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोश टीमों के माध्यम से युवा वॉलंटियर्स, एनसीसी कैडेट्स, जनप्रतिनिधि और

अधिकारी मिलकर जनता के बीच जाएंगे और टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ इसके उन्मूलन के प्रयासों के प्रबलत करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और संकल्प को इस मिशन से जोड़कर टीबी के खिलाफ लड़ाई को जन-जन

तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जब युवा शक्ति और जनभागीदारी एक साथ आगे बढ़ेंगी तो देश से टीबी की जड़ों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘टीबी हरेगा, देश जीतेगा’ के संकल्प



के साथ जोश टीमें देशभर में काम करेंगी और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगी। उन्होंने सभी युवाओं से इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनकर टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने और समाज को इस बीमारी से मुक्त करने के प्रयासों में योगदान देने

का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए ‘हम करके रहेंगे’ के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि यह विश्वास हमें हर चुनौती का सामना करने की ऊर्जा देता है। कुछ भी असंभव नहीं है और हर असंभव के भीतर संभव की संभावना

छिपी होती है। इसी विश्वास के साथ देश को टीबी-मुक्त बनाने और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। विकसित भारत का संकल्प तभी पूर्ण होगा, जब भारत स्वस्थ और समृद्ध होगा।

अपनी बात
संपादकीय



यह भाजपा का एजेंडा था और जो अभियान भारतीय मतदाता सूची को दुरुस्त करने पर केंद्रित होना चाहिए था वह जाने कब विदेशी नागरिक ढूंढने वाला बना दिया गया। फार्म 6 में बदलाव भी वोटर के मां-बाप की तलाश और उनसे जुड़े दस्तावेज तक इसी के चलते पहुंचा।

ज्ञानेन्द्र तो फंस गए हैं लेकिन भाजपा ?

भाजपा और केंद्र सरकार अगर अभी तक ज्ञानेश कुमार के पीछे खड़ी है तो यह उनके फायदे का सौदा रहा होगा। लेकिन इतना तय मानिए कि अगर ज्ञानेश कुमार फंसते हैं तो यह मेल बहुत दूर तक नहीं जाएगा। केन्द्रीय सत्ता इतनी आसानी से ऐसे मसलों से घिर जाए यह होता नहीं है। वह ज्ञानेश या किसी भी ऐसे अति महत्वाकांक्षी और कॅरियर के छोटे लाभों के लिए कायदे कानून को दरकिनार करने वालों से किनारा करने में देर नहीं लगाएगी। अपनी निर्णय प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि संबंधी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने के बाद से चुनाव आयोग भले आम लोगों को और संबंधित पक्षों के सामने अपनी बात रखने से बचना चाहता था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार और आयोग के सभी संबंधित लोगों को अदालत के सामने सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और फिर इस सफाई का कोई मतलब नहीं है कि अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील के इस तर्क को नहीं माना कि मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल निर्लंबित किया जाए और उनको काम करने से रोका जाए। अदालत यह फैसला नहीं कर सकती और बिना संबंधित पक्ष को सुने ऐसा फैसला न्यायोचित होता भी नहीं। लेकिन अदालत ने जिस तरह हर बात सफाई पूछी है और फार्म 6 के विवाद में खुद को घसीटें जाने से अपना पाला झटका है वह इस बात का संकेत है कि ज्ञानेन्द्र कुमार मुश्किल में हैं। अगर 14 फ़ैसलों पर शेष दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को उन्होंने दरकिनार किया था तो यह गंभीर दोष है और सरकार द्वारा चुनाव कानून में बदलाव करने की जगह खुद से फार्म 6 में बदलाव कर लिए तो यह अपराध की श्रेणी में ही आएगा। अगर वे आपत्तियों के बाद भी शेष दोनों आयुक्तों द्वारा सभी फ़ैसलों पर दस्तखत करने का प्रमाण ला देते हैं, जैसा कि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है, तो फिर अदालत उनके पक्ष में फैसला देगी। सवाल भाजपा के जवाब देने पर भी उठे हैं और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर भाजपा और एनडीए के लोग ही लगातार जवाब देते रहे हैं। उस हिसाब से इंडिया गटबंधन द्वारा चुनाव आयोग की घरेबंदी और देश भर में विरोध

प्रदर्शन का आयोजन करना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी लगातार इस सवाल को उठाते रहे हैं लेकिन उनका व्यवहार मुद्दे के अनुरूप पर्याप्त गंभीर नहीं दिखता। सारी गड़बड़



बोलकर भी चुनाव में भागीदारी करना और जीतने पर सरकार बनाने से लेकर खुशियां मनाना और हारने पर ईवीएम और आयोग पर दोष मढ़ना गंभीरता को खत्म करता है। लेकिन अदालती लड़ाई और राजनैतिक लड़ाई का फर्क हमको भी समझना होगा। अदालत तथ्यों और तर्कों के आधार पर फैसला करती है, राजनीति में हवा बनने बनाने की भी बड़ी भूमिका है और चुनाव आयोग की घरेबंदी से लेकर

सड़कों पर उतरना उसका हिस्सा है। जब भाजपा खुलकर आयोग का साथ दे रही है तो ज्ञानेश कुमार के फ़ैसलों के साथ केंद्र सरकार और भाजपा को जोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी तक राहुल ने सड़क की कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण को एक सामान्य प्रशासनिक अभियान की जगह घुसपैठिया-विरोधी मुहिम, अल्पसंख्यक-विरोधी मुहिम और कमजोर तथा कम पढ़े-लिखे या दस्तावेजों को संभालने और प्रस्तुत करने के मामले में कमजोर या लाचार लोगों के खिलाफ अभियान बना देना चुनाव आयोग भर का काम न था।

यह भाजपा का एजेंडा था और जो अभियान भारतीय मतदाता सूची को दुरुस्त करने पर केंद्रित होना चाहिए था वह जाने कब विदेशी नागरिक ढूंढने वाला बना दिया गया। फार्म 6 में बदलाव भी वोटर के मां-बाप की तलाश और उनसे जुड़े दस्तावेज तक इसी के चलते पहुंचा।

और नतीजा क्या निकाला? बांग्लादेशी या रोहिंगिया घुसपैठियों के पकड़े जाने का शायद ही कोई मामला सामने आया लेकिन मतदाता सूची से तेरह करोड़ नाम काट दिए गए। यह सब तब हुआ जब बिहार के बाद हर राज्य में राजनैतिक दलों द्वारा नए मतदाता सूची में नाम जोड़वाने और कटवाने का अभियान सा चलाया। मृत लोगों या पता बदलने वालों और दो जगह नाम वालों का नाम हटाना जरूरी था लेकिन उसके लिए कई राज्यों में तीस फ़ीसदी से भी ज्यादा नाम काट देना सिर्फ बीएलओ जैसे कर्मचारियों के वश का नहीं है। यह निर्देश आयोग और संभव है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से गया हो। इसी संभावना को पुख्ता राजनैतिक विमर्श बनाने की कोशिश कांग्रेस और विपक्ष कर रहे हैं। अब यह उनके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि वे इस काम को कहां तक पहुंचाते हैं।

भाजपा और केंद्र सरकार अगर अभी तक ज्ञानेश कुमार के पीछे खड़ी है तो यह उनके फायदे का सौदा रहा होगा। लेकिन इतना तय मानिए कि अगर ज्ञानेश कुमार फंसते हैं तो यह मेल बहुत दूर तक

नहीं जाएगा। केन्द्रीय सत्ता इतनी आसानी से ऐसे मसलों से घिर जाए यह होता नहीं है। वह ज्ञानेश या किसी भी ऐसे अति महत्वाकांक्षी और कॅरियर के छोटे लाभों के लिए कायदे कानून को दरकिनार करने वालों से किनारा करने में देर नहीं लगाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि कांग्रेस और विपक्ष का सड़क का आन्दोलन इतना दबाव बनाने में सफल हो जिसे भाजपा का नेतृत्व अपने लिए नुकसानदेह मानने लगे। यह दूर की बात लगती है लेकिन अदालती फैसला इस स्थिति को जल्दी भी लाने में मदद करेगा। अगली सुनवाई की तारीख ज्यादा दूर नहीं है और वहां आया जवाब काफी सारे संकेत देने लगेगा।

विपक्ष इस बात पर भी खुश हो सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सीधे ज्ञानेन्द्र कुमार की विदाई को मुद्दा बनाया है। उसका अभियान 10 अक्टूबर से चलेगा। इसके पहले लगने से दो अक्टूबर को जो कार्यक्रम किया उसमे मुंबई का कार्यक्रम काफी सफल रहा जबकि दिल्ली में पुलिस ने आंदोलनकारियों को लगातार खदेड़ा। इसमे सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के लोग ही नहीं वाम छात्र संगठन और योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे लोग भी थे। उसे और इस मांग को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सीटींग जज समेत काफी सारे प्रबुद्ध और नामी लोगों का समर्थन मिल रहा है उसे भी विपक्ष अपने आंदोलन का सहारा बना सकता है। पिछली बार कॉकरोच जनता पार्टी ने ही मोदी सरकार की और उनकी मजबूत छवि को तार-तार कर दिया था और धर्मन्त प्रधान को जाना पड़ा। लेकिन इसके लिए विपक्ष को बहुत सावधानी और समझ से काम करना होगा। उससे ज्यादा मुश्किल काम भाजपा के लिए है। अभी तक तो वह ज्ञानेन्द्र कुमार के हर काम का समर्थन कर दिया करती थी और सुप्रीम कोर्ट तक ने बंगाल चुनाव के समय लाखों मतदाताओं को निराश करते हुए अमले चुनाव में वोट डालने का मजाक कर दिया। इस बार ऐसा लगता नहीं। ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं लेकिन भाजपा फंसी है या नहीं यह आने वाले वक़्त में जल्दी ही पता चल जाएगा।

लोकतंत्र की परीक्षा और एसआईआर पर उठते सवाल

—सविन कुमार गोतम
देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने वाली संस्थाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर उठते सवाल चिंता का विषय हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार गंभीर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया के तहत 13 करोड़ से अधिक नाम मतदाता सूची से बाहर हो चुके हैं। यदि यह आंकड़ा सही है, तो यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा प्रश्न है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और उसमें मौजूद गलतियों को दूर करना बताया जाता है। लेकिन किसी भी पुनरीक्षण प्रक्रिया की विश्वसनीयता तभी कायम रह सकती है, जब उसके नियम, आंकड़े और निर्णय सार्वजनिक हों। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसलिए उसके हर बड़े फैसले की जानकारी राजनीतिक दलों, नागरिक संगठनों, मीडिया और आम जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखी जानी चाहिए। पारदर्शिता से बचने की कोई भी कोशिश संदेह को जन्म देती है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग एसआईआर से जुड़े सवालों का खुलकर जवाब नहीं दे रहा है। सबसे अधिक विवाद ऑनलाइन फॉर्म-6 में किए गए बदलाव को लेकर है। फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए किया जाता है। एसआईआर के दौरान इस फॉर्म में एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़े जाने की बात सामने आई। इसके तहत नए मतदाता को यह बताना होता है कि वह

स्वयं या उसके माता-पिता पिछली एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में मैप किए गए थे या नहीं। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और उन परिवारों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है, जिनके पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में गरीब, ग्रामीण, प्रवासी और वंचित समुदायों के लोगों को अपने नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में कठिनाई हो सकती है। यदि किसी नागरिक से ऐसे दस्तावेज या घोषणाएं मांगी जाती हैं, जिनकी व्यवस्था उसके लिए आसान नहीं है, तो वह मताधिकार से वंचित हो सकता है। फॉर्म-6 में हुए इस बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने विवाद को और गंभीर बना दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कथित तौर पर कहा कि अदालत ने किसी संशोधित फॉर्म-6 को मंजूरी नहीं दी है। इसके विपरीत चुनाव आयोग की ओर से यह दावा किया जाता रहा कि फॉर्म में बदलाव सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद किया गया। यदि अदालत की टिप्पणी और चुनाव आयोग के दावे में अंतर है, तो इसकी स्पष्ट व्याख्या आवश्यक है। यह केवल शब्दों का विवाद नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा मामला है। रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने भी इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी। यदि आयोग के भीतर ही किसी निर्णय को लेकर मतभेद मौजूद थे, तो उस पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे जनता को यह समझने में मदद मिलेगी कि निर्णय



किस आधार पर लिया गया और उसमें किन अधिकारियों की क्या भूमिका थी। संवैधानिक संस्थाओं में आंतरिक असहमति लोकतंत्र के लिए असामान्य नहीं है, लेकिन उसे छिपाने से संस्थागत भरोसा कमजोर होता है।

इहीं सवालों के चलते विपक्ष एसआईआर को रद्द करने की मांग कर रहा है। मंगलवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की कोशिश की। उनका उद्देश्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराना था। सांसदों के हथों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

वाले पोस्टर भी थे।

मार्च शुरू होते ही दिल्ली पुलिस ने सांसदों को रोक दिया और कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव, डेक ओ'ब्रायन और अभिषेक बनर्जी सहित अनेक सांसदों को बसों में बैधया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा भी अन्य सांसदों के साथ आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंच गए, जो चुनाव आयोग के कार्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। विपक्षी सांसदों ने वहीं धरना शुरू कर दिया और चुनाव आयोग के दूसरे प्रवेश द्वार से अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आगे नहीं

जाने दिया गया।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में कहा कि 300 से अधिक विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग तक पदयात्रा करके आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ये सांसद करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो चुनाव आयुक्त उनसे मिलने से क्यों बच रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने जा रहे जनप्रतिनिधियों को क्यों रोक रही है।

यह सवाल पूरी तरह जायज है। चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं, बल्कि देश की संवैधानिक चुनावी संस्था है। राजनीतिक दलों को अपनी आपत्तियां और शिकायतें सीधे चुनाव आयोग के सामने रखने का अधिकार है। आयोग किसी प्रतिनिधिमंडल से मिलना चाहता है या नहीं, यह प्रशासनिक निर्णय हो सकता है, लेकिन निर्वाचित सांसदों के साथ संवाद से पूरी तरह बचना लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं कहा जा सकता।

विपक्षी नेताओं ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज पर आपत्तियां पहली बार नहीं उठ रही हैं। उनके अनुसार, कई मौकों पर ऐसा लगता है कि आयोग सभी राजनीतिक दलों को समान दृष्टि से नहीं देख रहा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया। उनका सवाल था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इतनी कड़ी सुरक्षा

व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी।

लोकतंत्र में असहमति को दबाने के बजाय सुना जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के बीच मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों का उत्तर तथ्यों, दस्तावेजों और सार्वजनिक संवाद के माध्यम से दिया जाना चाहिए। यदि एसआईआर में किसी नागरिक का नाम हटाया गया है, तो उसके लिए अपील और सुधार की सरल व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि कितने नाम हटाए गए, किन कारणों से हटाए गए और प्रभावित नागरिकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का कितना अवसर दिया गया।

सरकार और चुनाव आयोग दोनों की जिम्मेदारी है कि वे लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखें। विपक्ष के आरोप सही हैं या नहीं, इसका निर्णय तथ्यों और स्वतंत्र जांच से होना चाहिए। लेकिन सवाल पूछने वालों को रोकना, मिलने का अवसर न देना और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध न कराना संदेह को और गहरा करता है।

लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है। यह नागरिकों के मताधिकार, संस्थाओं की निष्पक्षता, राजनीतिक असहमति के सम्मान और सार्वजनिक जवाबदेही पर आधारित व्यवस्था है। इसलिए एसआईआर से जुड़े सभी आंकड़े, नियम और निर्णय सार्वजनिक किए जाने चाहिए। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ खुला संवाद करना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा केवल सत्ता पक्ष या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर संवैधानिक संस्था और नागरिक की साझा जिम्मेदारी है।

पाकिस्तानियों को भारत में दी गई नागरिकता के मायने?

जब दो बॉर्डर राज्य, असम और पश्चिम बंगाल, का चुनाव इसी मसले के इर्दगिर्द घूमा, घुसपैठियों के अलावा भारत में कुछ वर्षों से एनआरसी और सीएए का भी शोर है



—स्मृति श्रीवास्तव
जगज्जननी मां तुझे नमन है,
भवतारिणी मां तुझे नमन।
ब्रह्मरूपिणी तुझे नमन है,
भयहारिणी मां तुझे नमन।

तू ही है परधाम निवासिनी,
मूलाधार निवासिनी तू।
अष्टमातुका योगिनी तू ही,
सकल कष्ट निवारिणी तू।

हे विश्वेश्वरी तुझे नमन है,
हे नारायणी तुझे नमन।
सर्वमंत्रमयी तुझे नमन है,
महातपा मां तुझे नमन।

दश विधा और नव दुर्गा तू,
सर्व सीमाघ्न दाहिनी तू।
तू ही शक्ति है, तू ही सौम्या,
मंगला व्याधि विनाशिनी तू।

हे कात्यायनी तुझे नमन है,
हे भवभामिनी तुझे नमन।
तपस्विनी मां तुझे नमन है,
हे शम्भवी मां तुझे नमन।

तू ही जयंती, तू ही काली,
सर्व शत्रु विनाशिनी तू।
तू ही शिवा है, तू ही धात्री,
चतुर्भुजा परमेश्वरी तू।

हे करुणामयी तुझे नमन है,
स्नेहसुधामयी तुझे नमन।
कृपादृष्टि और दयादृष्टि,
बरसाओ हम करते वंदन !!!



डॉ. रमेश ठाकुर
वरिष्ठ पत्रकार

पीलीभीत के जिस क्षेत्र में यह परिवार रहते आए हैं वह जगह कभी विरान होती थी। इन लोगों ने इसे रहने लायक बनाया और उबड़खाबड़ जगहों पर मेहनत करके उसे खेतीबाड़ी के लिए तैयार किया। आज इस क्षेत्र में अच्छी फसलें उगती हैं। सभी के पास कागजी दस्तावेजों के रूप में भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि पहले से मौजूद हैं। साथ ही लंबे वक़्त से मतदान भी करते आए हैं। लेकिन नागरिकता और मालिकाना हक से वंचित थे, जिसे मौजूदा योगी सरकार ने पूरा कर दिया। ये परिवार पीलीभीत जिले के अमरिया, न्यूरिया, शारदा डैम की तलहटी सहित आसपास के क्षेत्रों में बसे हैं

किसी पाकिस्तानी को आज के दौर में हिंदुस्तान में बसाना, उन्हें पनाह देना या फिर नागरिकता देनी वाली बात, शायद ही किसी के गले उतरे? बसाना तो दूर, ऐसा सोचना मात्र भी, सूरज का पूरब की जगह पश्चिम से निकलने जैसा माना जाएगा। पर, यह कोई कल्पना पिछले दिनों हकीकत में तब्दील हुई। भारत में 56 साल पहले आए पाकिस्तानियों को नागरिकता दी गई है। वह भी एकाध लोगों को नहीं, बल्कि हजारों को। सरकार ने पिछले महीने बकायदा एक रंगारंग कार्यक्रम कर, ढोल-गाढ़े बजाकर विस्थापित पाकिस्तानियों को नागरिकता प्रमाण पत्र बांटे। ताज्जुब यह भी है कि ऐसा चमत्कार हुकूमत ने ऐसे माहौल में किया, जब समूचे भारत में विभिन्न देशों के घुसपैठियों को निकालकर उन्हें खदेड़ने का अभियान केन्द्रीय व राज्य स्तरों पर छिड़ा हो। इस अभियान की बानगी हमने हाल में संपन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा। जब दो बॉर्डर राज्य, असम और पश्चिम बंगाल, का चुनाव इसी मसले के इर्दगिर्द घूमा। घुसपैठियों के अलावा भारत में कुछ वर्षों से एनआरसी और सीएए का भी शोर है। बावजूद इसके सरकार ने पाकिस्तानियों को नागरिकता देने का बड़ा जाखिम उठाया। सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? हालांकि, इस फैसले के सियासी मायने बहुतेरे हैं, जिसकी तस्वीर आने वाले दिनों में दिखाई देगी।

सरकार ने विस्थापितों को नागरिकता हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दी है। जिले का नाम है पीलीभीत जो नेपाल बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है जिसकी पहचान बांग्सी निर्माण के अलावा तराई क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। पीलीभीत को मिनी पंजाब भी कहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज, जैव-विविधता के अलावा विषय प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व तो है ही, धान की पैदावार के लिए भी जिला पूरे प्रदेश में



विख्यात है। सरकार ने जिन परिवारों को बसाने का फैसला किया है उनमें बंगाली हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं। भारत के नक्शे में देखें, तो पीलीभीत हिंदुस्तान के एक अलहदे छोर पर बसा है जहां करीब पांच दशक से भी ज्यादा पहले पाकिस्तान से आए विस्थापित लोग बस गए थे। तभी, से वह विभिन्न सरकारों ने नागरिकता मांगते आए हैं। सरकारी कागजों के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान से वर्ष 1959 से 1971 के बीच पाकिस्तान से पीड़ित होकर कुछ्क परिवार भारत आए थे। शुरूआत में यह परिवार कई राज्यों से भटकते रहे, कहीं ठिकाना नहीं मिला। आखिरकार उन्हें बाद में यही जिला सुप्रीद लगा। पीलीभीत के अलावा कुछ नागरिकता

रामपुर और बिजनौर में बसे विस्थापितों को भी दी गई है।

पीलीभीत के जिस क्षेत्र में यह परिवार रहते आए हैं वह जगह कभी विरान होती थी। इन लोगों ने इसे रहने लायक बनाया और उबड़खाबड़ जगहों पर मेहनत करके उसे खेतीबाड़ी के लिए तैयार किया। आज इस क्षेत्र में अच्छी फसलें उगती हैं। सभी के पास कागजी दस्तावेजों के रूप में भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि पहले से मौजूद हैं। साथ ही लंबे वक़्त से मतदान भी करते आए हैं। लेकिन नागरिकता और मालिकाना हक से वंचित थे, जिसे मौजूदा योगी सरकार ने पूरा कर दिया। ये परिवार पीलीभीत जिले के अमरिया, न्यूरिया, शारदा डैम की तलहटी सहित

आसपास के क्षेत्रों में बसे हैं। सरकार ने उन्हें खेती और आवास के लिए जमीन तो पहले से दी हुई हैं। लेकिन मालिकाना हक़ियत नहीं दी, जिसके लिए यह लोग दशकों जहोज़हद कर रहे थे। प्रत्येक चुनावों में इनसे के झूठा आश्वासन हुआ। पूर्ववर्ती बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने भी इनको नागरिकता दिलवाने का दिलासा दिया। पर, कुछ राजनैतिक अड़चनों के चलते वादा पूरा नहीं कर पाए।

बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके साथ वादा किया गया था, जिसे अब पूरा किया गया। प्रदेश सरकार की पहल पर सभी पीड़ित परिवारों को सूचीबद्ध करके नागरिकता और मालिकाना के प्रमाण बांटे गए हैं। नागरिकता करीब 2500 परिवारों को

दी गई है जिनकी कुल संख्या 15 हजार के आसपास है। ऐसा करके सरकार ने शायद विपक्षी दलों को बड़ा सियासी मुद्दा बैटै-बिटाए थमा दिया है। ये लोग वर्ष 1960 से 1975 के बीच धार्मिक प्रताड़ना के चलते पूर्वी बंगालादेश जो अब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है, से भारत आए थे और उत्तर प्रदेश के तराई के जिले पीलीभीत में आकर बसे। ये क्षेत्र पीलीभीत जिले की कलीनगर व पूरनपुर तहसीलों में आते हैं जहां ये करीब 25-26 गांवों में बसे हैं। पिछले महीने 29 जून को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिले में दौरा हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने इनको ना सिर्फ नागरिकता के प्रमाण पत्र बांटे, बल्कि मालिकाना हक के सरकारी कागज भी दिए।

यह फैसला चुनाव के ऐन वक़्त लिया गया। प्रदेश में मात्र 6-7 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए सरकार के इस निर्णय पर प्रदेश की राजनीति जमकर गर्माई हुई है। विपक्षी पार्टियों ने सीधे-सीधे एक बड़े चोटबैक को साधने का आरोप मौजूदा सरकार पर लगाया है। पाकिस्तानी विस्थापियों को बसाने का यह पहला चरण है, अभी दूसरा चरण शेष है। 35 हजार लोग और हैं जो बहराईच, बागबंकी, गोंडा, लखीमपुर, बिजनौर जैसे जिलों में बसे हैं। सभी की चिह्नित किया जा चुका है, अगले कुछ महीनों बाद इन्हें भी मुकम्मल नागरिकता देने का फैसला हो चुका है। सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रदेश के करीब सात-आठ जिलों में कुल 55 हजार विस्थापित पाकिस्तानियों की आबादी है, इनमें प्रत्येक वर्ष तेजी से इलाफा भी हो रहा है। 56 वर्ष पहले धार्मिक प्रताड़ना के रूप में मात्र 12 हजार 380 लोग आए थे। आबादी बढ़ने के पीछे इनका मक़सद था कि बड़ी आबादी से सरकारी को वोटिंग का लालच देकर किसी भी दल पर दबाव बना सकेंगे। कमोवेश, हुआ भी वैसा ही। अपने योजनाओं में यह लोग आज सफल हुए हैं।

संक्षिप्त डायरी

लभूत सुविधाओं की मांग को लेकर

अधिवक्ताओं ने किया कार्य का बहिष्कार

एजेंसी
देवरिया। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के कलेक्ट्रेट परिसर में मूलभूत सुविधाओं की कमी के विरोध में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने गुरुवार को न्यायालय के कार्य का बहिष्कार किया। दोपहर करीब एक बजे बड़ी संख्या में अधिवक्ता कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए और पेयजल, आरओ, शौचालय समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप मिश्रा, प्रानु मिश्रा, संजय मिश्रा समेत दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में पर्याप्त आरओ की व्यवस्था नहीं है। शौचालय समेत अन्य जरूरी सुविधाओं का भी अभाव है। कलेक्ट्रेट में रोजाना बड़ी संख्या में अधिवक्ता और वादकारी अपने काम के सिलसिले में पहुंचते हैं। सुविधाएं नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या और गंभीर हो जाती है। दूर-दराज से आने वाले वादकारियों को पानी और शौचालय के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। उन्होंने परिसर में पर्याप्त आरओ लगाने, शौचालय की व्यवस्था कराने और अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त कराने की मांग की। अधिवक्ताओं ने संबंधित अधिकारियों से समस्याओं का जल्द और स्थायी समाधान कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि न्यायिक कार्य के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले अधिवक्ताओं और वादकारियों को जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर आगे की रणनीति तय करने की चेतावनी दी गई।

10 से 25 अक्टूबर तक मिलेगा नि:शुल्क

खाद्यान्न, ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

एजेंसी
औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के तहत जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को अक्टूबर माह का नि:शुल्क खाद्यान्न 10 से 25 अक्टूबर तक वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार उचित दर दुकानों पर ई-वेजिंग लिंकड ई-पांस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणिकरण के बाद खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को प्रति राशनकार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल शामिल है। वहीं पात्र गृहस्थी (सफेद कार्ड) के लाभार्थियों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें दो किलोग्राम गेहूं, दो किलोग्राम चावल और एक किलोग्राम मक्का शामिल है। मक्का का वितरण उचित दर विक्रेता के पास उपलब्ध मात्रा रहने तक किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण पर्यवेक्षण अधिकारी एवं नोडल अधिकारी की देखरेख में करया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्रचलित राशनकार्डों में जिन यूनिटों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, उनके लिए आवर्तित खाद्यान्न का आपूर्ति शासन की ओर से निर्लंबित कर दी गई है। ऐसे में जिन राशनकार्डधारकों अथवा उनके परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी लॉन्ग है, वे राशन वितरण के दौरान अपने उचित दर विक्रेता के माध्यम से ई-पांस मशीन पर अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करा लें। इससे आगामी माह में संबंधित यूनिटों को आवश्यक वस्तुओं का लाभ मिल सकेगा। राशन वितरण से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर उपभोक्ता आपूर्ति विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 अथवा हेल्पलाइन नंबर 1967/144445 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बैठक

कर बांटा पूर्व पदाधिकारियों का सुख-दुख

एजेंसी
वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वाराणसी में दो दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन रोहनिया में गोकुल धाम रिसॉर्ट में पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके सुख-दुख को बांटा। बैठक में पूर्व पदाधिकारियों ने बहुत समय बाद मिले अपने साथियों को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। इस दौरान पूर्व पदाधिकारियों ने भाजपा में किए गए कार्यों की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देते हुए उन्हें पुनः सक्रिय करने की मांग की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बैठक में कहा कि काशी क्षेत्र के तीन टर्म के पूर्व जिलाध्यक्षों और पूर्व में क्षेत्र एवं प्रदेश में कार्यरत पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनके पार्टी कार्यों की जानकारी ली है। संगठन की वषों तक अपनी निष्ठावान सेवाएं देने वाले हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के अनुभव और सुझावों से पार्टी को संदेव नई ऊर्जा और मजबूती मिलती है। यह बैठक परिवार के अनुभवी सदस्यों की बैठक थी। इस दौरान पूर्व पदाधिकारी शिवनाथ यादव ने कहा कि वर्तमान समय के कार्यकर्ताओं से अभी उनका ठीक से परिचय नहीं है। इस बैठक में पुराने कई कार्यकर्ता मिले हैं, जिनके साथ हमने कार्य किया है। पूर्व कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की बैठक होते रहनी चाहिए। इससे नई ऊर्जा मिलती है।,इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरशिया, सह प्रदेश प्रभारी जगदीश पटेल और प्रभारी रमेश सिंह उपस्थित रहे।

रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव,जांच में जुटी पुलिस

एजेंसी
फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में मऊ दरबाजा थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर गुरुवार को एक महिला का शव पड़ा पाया गया। रसीदपुर रेलवे लाइन गेट में के माध्यम से सूचना दी गई गेट नम्बर 144/9/बी गांव की हथियापुर क्रासिंग से 03 किलामीटर रसीदपुर गांव के पास रेलवे लाइन पर एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पहुंचे लोगों ने महिला की शिनाख्त नेम देवी(45) पत्नी ऋषिराम निवासी शमशेर नगर थाना मऊ दरवाजा जनपद फर्रुखाबाद के रूप में की। बताया गया कि ट्रेन संख्या 15040 फर्रुखाबाद एक्सप्रेस कासगंज जाने वाली ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मृत्यु हो गई है। मौके पर पहुंचे पति ऋषिराम भी मृत महिला को शिनाख्त अपनी पत्नी के रूप में की है। थानाध्यक्ष अजब सिंह ने बताया कि महिला की मौत कैसे हुई है, इसका पता लगाया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

आयुष आपके द्वार शिविर में 107

मरीजों का हुआ उपचार

एजेंसी
औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में सेवा संकल्प अभियान के तहत गुरुवार को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैदरपुर की ओर से विकासखंड अजीतमल के महाराजपुर में आयुष आपके द्वार आउटरीच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन होत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार के निदेशन में किया गया। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैदरपुर के चिकित्साधिकारी डॉ. जितेंद्र कुमार वर्मा एवं समस्त स्टाफ ने ग्रामीणों को बदलते मौसम के अनुसार दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार-विहार और उचित जीवनशैली के प्रति जागरूक किया। चिकित्साधिकारी ने मौसम में बदलाव के दौरान होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताए। शिविर में मुख्य रूप से त्वचा रोग, उदर रोग, मधुमेह, हृदय रोग, श्वास-कास एवं अतिशय आदि रोगों से पीड़ित मरीजों की जांच कर उन्हें चिकित्सा परामर्श दिया गया।

विद्यार्थी परिषद ने लगाया कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण केंद्र में अनियमितता का आरोप,एसडीएम लहरपुर को सौंपा ज्ञापन

एजेंसी
सीतापुर । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जनपद सीतापुर में लहरपुर तहसील के कार्यकर्ताओं ने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित एक प्रशिक्षण केंद्र में कथित अनियमितताओं एवं सरकारी मानकों के उल्लंघन के संबंध में उपजिलाधिकारी लहरपुर धामिनी एम दास को गुरुवार को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष एवं स्थलीय जांच कराए जाने की मांग की। ज्ञापन में अभाव्तिप कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि कौशल विकास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। ऐसे में यदि किसी प्रशिक्षण केंद्र में निर्धारित मानकों की अनदेखी अथवा



अभिलेखों और वास्तविक व्यवस्था में अंतर की शिकायत सामने आती है, तो उसका गंभीरता से संज्ञान लिया जाना आवश्यक है। जानकारी हो कि लहरपुर तहसील के ताहपुर में भारती बाल संस्था के अंतर्गत संचालित केंद्र पर अनियमितता एवं दुर्व्यवहार के आरोप विद्यार्थी परिषद

ने लगाए हैं। ज्ञापन में अल्पवयस्क प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन एवं केंद्र पर कार्यरत होने, प्रशिक्षकों की निर्धारित योग्यता एवं अभिलेखों में कथित विसंगति, निर्धारित संख्या की तुलना में कम प्रशिक्षकों की उपलब्धता तथा प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित सामग्री एवं वर्दी उपलब्ध

नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की नींव, संस्कृत विश्वविद्यालय से निकली साइकिल यात्रा, 100 सप्ताह तक चलेगा जागरुकता अभियान

निकली साइकिल यात्रा, 100 सप्ताह तक चलेगा जागरुकता अभियान

एजेंसी
वाराणसी। नशामुक्त युवा-विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से भव्य साइकिल यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय आह्वान के अनुरूप आयोजित नशा मुक्त युवाझ्विकसित भारत के लिए संम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की निधार्तित योग्यता एवं अभिलेखों में कथित विसंगति, निर्धारित संख्या की तुलना में कम प्रशिक्षकों की उपलब्धता तथा प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित सामग्री एवं वर्दी उपलब्ध

लिखी तख्तियां और बैनर रहे।

नशामुक्त युवा विकसित भारत की वास्तविक शक्ति : कुलपति कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के शरीर और मन को कमजोर नहीं करता, बल्कि इसका अमर परिवार, समाज और राष्ट्र की सामूहिक शक्ति पर भी पड़ता है। स्वस्थ, संस्कारवान, जागरूक और नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की वास्तविक शक्ति हैं। न्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है। युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और रचनात्मक क्षमता को सकारात्मक दिशा देकर राष्ट्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए जरूरी है कि युवा नशे से दूर रहकर ज्ञान, संस्कार, नवाचार, खेल, सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ें। कुलपति ने कहा कि नशामुक्ति केवल व्यक्तिगत जीवनशैली का विषय नहीं, बल्कि परिवार की सुख-

शांति, समाज के स्वास्थ्य और राष्ट्र की प्रगति से जुड़ा सामाजिक दायित्व है। उन्होंने युवाओं से स्वयं नशामुक्त रहने के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि युवा नशामुक्ति को जीवन का संकल्प बनाएं तो इसका सकारात्मक प्रभाव परिवार और समाज तक पहुंचेगा। इन मांगों से गुजरी साइकिल यात्रा साइकिल यात्रा विश्वविद्यालय के मुख्य भवन से शुरू होकर लहराबीर, आजाद पार्क, मैदागिन चौराहा, पटेल धर्मशाला और तेलियाबाग होते हुए पुनः विश्वविद्यालय परिसर की ओर रवाना हुई। मार्ग में युवाओं ने लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया और स्वस्थ एवं जिम्मेदार समाज के निर्माण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और युवाओं ने नशे से दूर रहने तथा समाज को भी नशामुक्त बनाने के लिए जागरूक करने का संकल्प लिया। अभियान से युवाओं को डिजिटल माध्यम से भी जोड़ा गया।

काँग्रेसियों ने निकाली पदयात्रा, क्वींस कॉलेज के गेट पर गंगाजल छिड़ककर किया शुद्धिकरण

एजेंसी

वाराणसी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग को लेकर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में गुरुवार को विरोध पदयात्रा निकाली गई। राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस ने इसे काफ़ी दिवस के रूप में मनाते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग उठाई। पदयात्रा में मैदागिन स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा से शुरू होकर लहुराबीर स्थित आजाद पार्क होते हुए क्वीन्स कॉलेज के मुख्य द्वार तक पहुंची। क्वीन्स कॉलेज के मुख्य द्वार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मां गंगा के जल का छिड़काव कर प्रतीकात्मक शुद्धीकरण किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुख्य निर्वाचन



आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसी संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है। जिस काशी और निष्पक्षता संस्थान ने उन्हें शिक्षा व संस्कार दिए, आज उन्हीं की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी के विरोध में शुद्धीकरण कार्यक्रम किया गया। पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग

को लेकर नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे बड़ी ताकत है और मताधिकार से किसी भी तरह का खिलवाड़ जनता के अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता जरूरी : राघवेंद्र चौबे महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के प्रति जनता के मन में संदेह पैदा होना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।



किया गया। पिता मनोज प्रजापति ने मुखाग्नि दी। बेटे को अंतिम विदाई देते समय परिजन बद्धवास हो गए। लार थाना क्षेत्र के चुरिया गांव निवासी अनिकेत सिंह का गांव के समीप सरयू नदी के घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। छोटे भाई अंकित ने मुखाग्नि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिचित मौजूद रहे। लार थाना क्षेत्र के कोहरा गांव निवासी आनंद यादव का भी गांव के समीप सरयू नदी के घाट पर

चुनाव आयोग के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंककर जताया विरोध

एजेंसी
वाराणसी। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को वाराणसी कचहरी मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा प्रदेश सचिव लालू यादव के नेतृत्व में जुटे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और आयुक्त का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और मताधिकार की रक्षा की मांग की। उनका कहना था कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर जनता के बीच उठ रहे सवालों का जवाब चुनाव आयोग और जिम्मेदार संस्थाओं को देना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि

वीरेंद्र सिंह के आह्वान पर प्रदर्शन सपा प्रदेश सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और चंदौली सांसद विरेंद्र सिंह के आह्वान पर प्रदेशभर में चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कचहरी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। ह्दइस्तीफा होने तक जारी रहेगा आंदोलनह लालू यादव ने कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ता जनता के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। चंदौली से सपा सांसद विरेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के जरिये बीजेपी ने वोटों की चोरी की। इसके जरिये ही



घोषित कर दिया गया। सरकार को न उन्हें रोजगार देना होगा और न ही नौकरी। इस तरह से सरकार लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। समाजवादी पार्टी आम आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए यह आंदोलन चला रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने

कहा कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आंदोलन जारी रखने का संकल्प जताते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर जेल जाना पड़े या पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़े, पार्टी कार्यकर्ता संघर्ष करते रहेंगे।

संक्षिप्तसमाचार

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को झटका

बाहर हुए चैपमैन और फॉल्क्स

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड को अपने घर में भारत के खिलाफ 22 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। सीरीज से पहले कीवी टीम को दो बड़े झटके लगे हैं। मार्क चैपमैन और जैक फॉल्क्स चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। चैपमैन को जांघ में खिंचाव है, जबकि फॉल्क्स कूल्हे की चोट से



परेशान हैं। इन दोनों का सीरीज से बाहर होना न्यूजीलैंड को मुश्किल में डाल सकता है। इसकी वजह दोनों खिलाड़ियों का इस फॉर्मेट में अनुभव और प्रदर्शन है। मार्क चैपमैन को पिछले महीने युरोपियन टी20 लीग खेलने के दौरान हेमरिड्रम में चोट लगी थी। उनके भारत के खिलाफ वनडे सीरीज तक ठीक होने की उम्मीद है। वहीं, फॉल्क्स को अभ्यास के दौरान दाहिने कूल्हे में चोट लग गई। फॉल्क्स की वापसी कब तक होगी, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। चैपमैन और फॉल्क्स की जगह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में जोश क्लार्कसन और तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर को शामिल किया गया है।

शुभंकर ने कपिल देव इन्विटेशनल टूर चैंपियनशिप में चार-शॉट की बढ़त बनाई

ग्रेटर नोएडा। शुभंकर शर्मा ने गुरुवार को कपिल देव इन्विटेशनल टूर चैंपियनशिप के दूसरे राउंड के बाद सात-अंडर 65 का स्कोर करके चार-शॉट की बढ़त हासिल कर ली। 12 करोड़ रुपये की इनामी राशि वाली यह प्रतियोगिता ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स गोल्फ एंड स्पा रिजॉर्ट में जारी है। चंडीगढ़ के 30 वर्षीय गोल्फर (68-65) ने दिन की शुरुआत पिछले दिन के लीडर शौर्य भट्टाचार्य से दो स्ट्रोक पीछे रहकर की थी। उन्होंने एक ईगल, सात बर्डी और दो बोगी के



साथ 11-अंडर 133 का स्कोर हासिल किया। डीपी वर्ल्ड टूर पर दो बार जीत हासिल कर चुके शुभंकर ने अप्रैल में पीजीटीआई के बोल्डर्स वलासिक में जीत हासिल की थी, जिससे उनका प्रोफेशनल खिताब जीतने का आठ साल का इंतजार खत्म हुआ था। चंडीगढ़ के ब्रशवरपाल सिंह (72-65) ने शुभंकर के बराबर दिन का सबसे कम स्कोर बनाया। उनके सात-अंडर 65 के स्कोर में आठ बर्डी और एक बोगी शामिल थी, जिससे वे पिछले दिन संयुक्त 11वें स्थान से ऊपर उठकर सात-अंडर 137 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए।



हरमनप्रीत कौर की सबसे बड़ी विरासत वनडे विश्व कप 2025 का खिताब है: अंजुम चोपड़ा

‘मैंने हरमन को एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर बढ़ते देखा’

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा का मानना है कि हाल ही में कप्तानी छोड़ने वाली हरमनप्रीत कौर की सबसे बड़ी विरासत घरेलू धरती पर वनडे विश्व कप 2025 जीतना होगा। चोपड़ा ने कहा कि कौर टीम को जिस टीम से मिली थी, उससे कहीं ज्यादा मजबूत, अनुभवी और आत्मविश्वासी टीम के तौर पर छोड़कर गई हैं। अंजुम चोपड़ा ने आईएनएस से बात करते हुए कहा, ‘एक लीडर के तौर पर हरमनप्रीत की सबसे बड़ी पहचान हमेशा 2025 में वनडे वर्ल्ड कप जीतना रहेगी। उस टूर्नामेंट में उनकी बैटिंग, लीग मैच, सेमीफाइनल और फाइनल में, और कैसे टीम सभी के योगदान से वहां तक पहुंची। यह सिर्फ हरमन की वजह से नहीं था। हर खिलाड़ी के योगदान से हरमन वह ताज उठा पाई और भारत जीत सका। हरमन का कद इस टीम के साथ बढ़ा है, खासकर पिछले साढ़े तीन सालों में, जब से उन्होंने वनडे की कप्तानी संभाली है। पहले, हम टी20 बहुत कम खेलते थे और शेड्यूल में ज्यादा वनडे गेम होते थे। हाल के वर्षों में यह बदल गया है। अब अधिकांश द्विपक्षीय दौरों में वनडे से ज्यादा टी20 होते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘मैंने हरमन को एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर बढ़ते देखा है। उनकी विरासत हमेशा इस बात से

मापी जाएगी कि उन्होंने कहां से कप्तान संभाली और कहां छोड़ी। वनडे फॉर्मेट में इंडियन टीम वर्ल्ड चैंपियन है। जब उन्होंने कप्तान संभाली थी, तब की तुलना में यह टीम कहीं

आगे बढ़ी है। हरमनप्रीत कौर की सबसे बड़ी विरासत वनडे विश्व कप 2025 का खिताब है: अंजुम चोपड़ा

उनके आस-पास की चीजें काफी बदल गई हों। मैंने उनमें कभी भी जल्दबाजी वाला पहलू नहीं देखा। उन दिनों से लेकर अब तक मैंने हरमनप्रीत कौर में हमेशा एक शांत स्वभाव देखा है। एक कप्तान के तौर पर, अगर मैदान में कोई मामूली कोशिश करता है-जैसे गेंद को रोकने में नाकाम रहना, उसे जल्दी वापस न फेंकना या एक अतिरिक्त रन देना-तो वह उस व्यक्ति को मैदान पर ही मौका देती हैं, चाहे कैमरे उन्हें पकड़ें या नहीं। लेकिन जिस पल वही व्यक्ति अच्छा स्टॉप करता है, विकेट लेता है या कैच लेता है, वह सबसे पहले दौड़कर उसकी तारीफ करती हैं। मैंने इतने सालों में कप्तान हरमन के दोनों पहलू देखे हैं। एक व्यक्ति के तौर पर हरमनप्रीत नहीं बदली हैं और यही उनकी खूबसूरती है। ‘ग्लोबल इवेंट्स में टीम इंडिया के जीत की दामेदार बनने की प्रक्रिया के सवाल पर अंजुम ने कहा, ‘यह इसलिए बदला है क्योंकि हमने सकारात्मक तरीके से परिणाम देखना शुरू कर दिया है। मैं यह नहीं कह रही कि पहले के कप्तान परिणाम नहीं देते थे, लेकिन जब हरमन ने टीम संभाली, तो गुयाना में 2018 वर्ल्ड कप में भी, मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच याद है, उन्होंने शतक लगाया था।

अंजुम ने कहा- मैंने 2025 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी लगातार कहा है कि इंडिया के पास बॉलिंग की कमी है। जीत पक्की करने के लिए उन्हें दो विकेट लेने के लिए शेफाली को लाना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने वह वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हमारे पास अभी भी बॉलिंग डेथ की कमी थी। आज भी, हम क्रांति गौड़ जैसे एक फास्ट बॉलर के साथ खेलते हैं, और नंदिनी शर्मा अभी-अभी आई हैं।’ हरमनप्रीत के इस्तीफे वाले पोस्ट में त्याग शब्द पर अंजुम ने कहा, ‘सबसे बड़ा त्याग जो आप करते हैं, वह है खेलने की अपनी शैली को किनारे रखना। कभी-कभी आप नंबर तीन पर बैटिंग करना चाहते हैं, लेकिन टीम को आपसे नंबर चार या ओपनिंग करने की जरूरत होती है, इसलिए आप वह मुश्किल रोल निभाते हैं। आपको टीम के फायदे को अपने फायदे से पहले रखना होगा। हो सकता है आप बॉलिंग करना चाहें या न करना चाहें, या टीम को आपकी जरूरत बाउंड्री लाइन पर हो सकती है - ये छोटी-छोटी बातें हैं।

एचडी फायर प्रोटेक्ट का आईपीओ 13 अक्टूबर को खुलेगा

- निवेशक 15 अक्टूबर तक इसमें बोली लगा सकेंगे

नई दिल्ली।

आग से सुरक्षा उपकरण बनाने वाली अग्रणी कंपनी एचडी फायर प्रोटेक्ट प्राइमरी मार्केट में एक बार फिर उत्साह लाने वाली है। कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) लेकर आ रही है, जिसका लक्ष्य करीब 712 करोड़ रुपये जुटाना है। यह पब्लिक इश्यू 13 अक्टूबर को खुलेगा और निवेशक 15 अक्टूबर तक इसमें बोली लगा सकेंगे। आईपीओ के लिए प्रति शेयर 258 से 271 रुपये का प्राइस बैंड तय है, जहां एक लॉट में 55 शेयर (लगभग 14,905 रुपए का निवेश) मिलेंगे। यह पूरा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) है, यानी कंपनी को सीधा कोई फंड नहीं मिलेगा, बल्कि मौजूदा शेयरधारक हिस्सेदारी बेचेंगे। आईपीओ के बाद प्रमोटरों की हिस्सेदारी 100 फीसदी से घटकर 85 फीसदी रह जाएगी, जिससे कंपनी का मूल्यांकन लगभग 4,749 करोड़ रुपए होगा। एचडी फायर प्रोटेक्ट आग बुझाने वाले उपकरण बनाती है और भारत सहित 90 से अधिक देशों में कारोबार करती है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी की परिचालन आय 489 करोड़ रुपए और लाभ 117 करोड़ रुपए रहा। विश्लेषक इस आईपीओ को लेकर सकारात्मक हैं। वे कंपनी के मजबूत मुनाफे, कर्मचारी स्थिति और अंतरराष्ट्रीय विस्तार की संभावनाओं को इसकी ताकत मानते हैं। हालांकि, ग्राहकों व सप्लायरों पर निर्भरता, साथ ही कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे जोखिम भी मौजूद हैं। लंबी अवधि के लिए, कंपनी के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों को देखते हुए विश्लेषक इस आईपीओ पर बुलिश हैं।

सिनेपोलिस और कोका-कोला पर 85,000 का जुर्माना

पटना।

बिहार की राजधानी पटना में उपभोक्ता आयोग ने सिनेपोलिस सिनेमा और कोका-कोला कंपनी पर 85,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

यह जुर्माना सिनेमा हॉल में एक दर्शक को अपनी पानी की बोतल ले जाने से रोकने और परिसर के अंदर अत्यधिक कीमत पर पैकेज्ड पानी खरीदने के लिए मजबूर करने के अनुचित व्यापार व्यवहार के

कारण लगाया गया है।

यह फैसला शिकायतकर्ता रजत तिवारी द्वारा कंज्यूमर कोर्ट में दायर केस के लगभग एक दशक बाद आया है। मामला 23 सितंबर 2016 का है, जब एक यहां के एक स्थानीय निवासी सिनेपोलिस सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए थे। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें अपनी पानी की बोतल अंदर ले जाने से रोक दिया, जिसके बाद उन्हें परिसर में किनारे की बोतल 50 रुपए में खरीदनी पड़ी, जबकि

बाहर इसका खुदरा मूल्य 20 रुपए था। इस घटना के बाद तिवारी ने अनुचित व्यापार व्यवहार और मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान, सिनेपोलिस ने मूल्य निर्धारण में अपनी भूमिका से इनकार किया, वहीं कोका-कोला ने अपनी कीमतों को नियमों के अनुरूप बताया। हालांकि, आयोग की पीठ ने दोनों कंपनियों की दलीलों को खारिज करते हुए दर्शक को बाहर से पानी लाने से रोकने और एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग कीमत वसूलने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने निर्देश दिया है कि 45 दिनों के भीतर निर्धारित राशि जमा न करने पर ब्याज लगाया जाएगा। यह आदेश उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और सार्वजनिक स्थलों पर अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

फील्डमार्शल ने उतारे भारत के पहले टीआरईएम वी एकल-सिलेंडर डीज़ल इंजन

मुंबई।

प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी फील्डमार्शल पीएम डीज़ल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 15 और 18 अक्षरशक्ति (हॉर्स पावर) श्रेणी में नए एकल-सिलेंडर डीज़ल इंजन पेश किए हैं। कंपनी का कहना है कि ये भारत के पहले एआरएआई-अनुमोदित और टीआरईएम वी-मानकों का पालन करने वाले (कंप्लायंट) इंजन हैं, जो देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति है। ये नए इंजन विशेष रूप से छोटे ट्रैक्टरों और कृषि मशीनों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें उन्नत तकनीक, बेहतर ईंधन दक्षता और टिकाऊपन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनका सुसंहत (कॉम्पैक्ट) डिज़ाइन खेती से जुड़े विभिन्न कार्यों में इनके उपयोग को आसान बनाता है। इन इंजनों में भारत में विकसित एर्जास्ट गैस रीसर्कुलेशन (ईजीआर) प्रणाली शामिल की गई है, जो उत्सर्जन को कम करने और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने में मदद करती है। यह प्रणाली नए टीआरईएम वी उत्सर्जन मानकों का पालन सुनिश्चित करती है। कंपनी अब उन्नत इंजन, ट्रैक्टर व कृषि मशीनीकरण समाधान विकसित करने पर केंद्रित है, साथ ही कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, जल समाधान और बुनियादी ढांचे में विस्तार की भी योजना है।

हॉरर थ्रिलर प्रोजेक्ट से जुड़े अजय देवगन

अजय देवगन की अपकमिंग हॉरर थ्रिलर फिल्म का आधिकारिक टाइटल सामने आया है। इस फिल्म के निर्देशक रोहित जुगराज हैं। पहले इस प्रोजेक्ट को ‘गृह प्रवेश’ के नाम से जाना जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस फिल्म का नाम ‘सूर्य प्रकाश’ रखा गया है।

किससे प्रेरित है कहानी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सुपरनेचुरल थ्रिलर एक रहस्यमयी और नैतिक रूप से जटिल दुनिया को दिखाएगी, जिसमें देवगन एक ऐसा किरदार निभाएंगे जो उनकी हालिया फिल्मों के किरदारों से बिल्कुल अलग होगा। कहा जाता

है कि इसकी कहानी गरुड़ पुराण से प्रेरित है, जो एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। यह ग्रंथ पारंपरिक रूप से भगवान विष्णु और पक्षियों के राजा गरुड़ के बीच बातचीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ‘सूर्य प्रकाश’ टाइटल इस कहानी में रहस्य और रोमांच की एक और परत जोड़ता है, जिसमें हॉरर, मिस्ट्री और सस्पेंस का मिश्रण होने की उम्मीद है। फिल्म का प्रोडक्शन दो सितंबर को शुरू हुआ और इसके नवंबर तक चलने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक, मेकर्स इसे 2027 की दूसरी छमाही में सिनेमाघरों में रिलीज करने का लक्ष्य बना रहे हैं। इस फिल्म को पैनेरमा स्टूडियोज के कुमार मंगत और अभिषेक पाठक, देवगन फिल्मस के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं।

रोहित जुगराज का

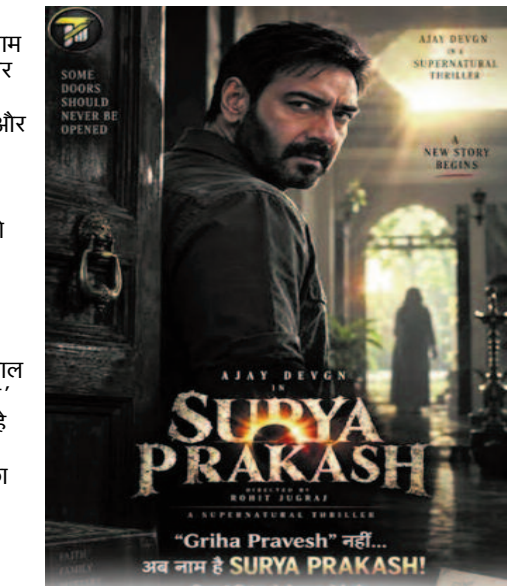
हॉरर जॉनर से नाता

‘सूर्य प्रकाश’ के निर्देशक रोहित जुगराज का

हॉरर जॉनर से पुराना नाता रहा है। उन्होंने 2003 में अजय देवगन की फिल्म ‘भूत’ में राम गोपाल वर्मा के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद जुगराज ने ‘सरदारजी’ फिल्में डायरेक्ट कीं और ‘ये काली काली आंखें’ और ‘चमक’ जैसे स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। ‘सूर्या प्रकाश’ पर देवगन के साथ उनका काम सुपरनेचुरल जॉनर में एक और कोशिश है, जो इस बार एक मिस्ट्री-थ्रैसर कहानी के जरिए सामने आएगी।

अजय देवगन का वर्कफ्रंट

अजय देवगन जल्द ही रोहित शेंद्री की ‘गोलमाल 5’ में भी नजर आएंगे। यह फिल्म ‘गोलमाल’ सीरीज की पांचवीं फिल्म है। खास बात यह है कि इस फिल्म से अक्षय कुमार भी जुड़े हैं। बताया जाता है कि वह इस फिल्म में विलेन का किरदार करेंगे। अजय देवगन ‘दृश्यम: द कन्वूजन्’ की तैयारी कर रहे हैं, जो इस पॉपुलर थ्रिलर फ्रैंचाइजी का अगला चेंप्टर है।



नेपाल में फिर कांपी धरती: पश्चिमी क्षेत्र में आया 4.1 तीव्रता का भूकंप, कई जिलों में महसूस किए गए झटके

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के पश्चिमी हिस्से में बुधवार रात 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके बजुरा के साथ आसपास के कई जिलों में भी महसूस किए गए। हालांकि, अभी तक कहीं से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के मुताबिक, भूकंप बुधवार रात स्थानीय समयानुसार 9:37 बजे आया। भूकंप का केंद्र सुदूरपश्चिम प्रांत के बजुरा जिले की बुधिगंगा नगरपालिका-10 में जमीन के भीतर था। यह जगह राजधानी काठमांडू से करीब 750 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भूकंप के झटके बजुरा के अलावा पड़ोसी बाजहाग, कालिकोट और अछाम जिलों में भी महसूस किए गए। अचानक धरती हिलने से इन इलाकों में लोगों को भूकंप का अहसास हुआ, हालांकि फिलहाल किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। नेपाल में सालभर छोट-बड़े भूकंप आते रहते हैं। हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने की वजह से यह देश दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय इलाकों में शामिल है। नेपाल का बड़ा हिस्सा भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में आता है, जिसके चलते यहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है।

क्रिस्टा पाइक की नाकाम कोशिश के बाद अमेरिका में पहली फांसी

टेक्सास , एजेंसी। टेक्सास में 46 वर्षीय जमाल हॉवर्ड को बुधवार शाम घातक इंजेक्शन देकर फांसी दी गई। वह इस साल अमेरिका में फांसी दिए जाने वाला 30वां व्यक्ति और टेनेसी में क्रिस्टा पाइक को घातक इंजेक्शन देने की नाकाम कोशिश के बाद देश में फांसी पाने वाला पहला कैदी है। हंट्सविले की जेल में पेंटेगॉनबिल्ड की घातक खुराक दिए जाने के बाद हॉवर्ड को रात 8:03 बजे मृत घोषित किया गया। उसे 2000 में सिसबी शहर के एक स्टोर में डकैती के दौरान 42 वर्षीय कर्मचारी विकी स्वाटआउट की गोली मारकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। घटना की निगरानी कैमरे की फुटेज भी अदालत में सबूत के तौर पर पेश की गई थी। फांसी से पहले 70 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हॉवर्ड अधिकारियों से बातचीत करता रहा और प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछता रहा। अंतिम बयान में उसने पीड़िता के परिवार से माफ़ी मांगी।

दो करोड़ लोगों से लिया शुल्क, गूगल के खिलाफ ब्रिटेन में मुकदमा शुरू

लंदन, एजेंसी। प्ले स्टोर पर पेड सुविधा, गेमिंग आइटम या इन-ऐप सब्सक्रिप्शन पर ऐप डेवलपर्स से 30% तक की फीस लेने के मामले में गूगल को ब्रिटेन में बड़ा झटका लगा है। लंदन की अदालत में इस मामले पर कंपनी के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया है। मुकदमे का मुख्य आरोप यह है कि गूगल के इस भारी कमीशन के कारण ऐप डेवलपर्स को अपने ऐप्स और सर्विसेज के दाम बढ़ाने पड़े। मामले की अनुवाई कर रही उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ लिज कोल का कहना है कि ब्रिटेन के लगभग 2 करोड़ उपभोक्ताओं ने अनजाने में इन छिपे हुए शुल्कों के कारण ऐप्स और गेम्स के लिए ज्यादा कीमत चुकाई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि गूगल ने मोबाइल बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का गलत इस्तेमाल (एकाधिकार का दुरुपयोग) किया है, इसलिए ग्राहकों का पैसा वापस मिलना चाहिए। वहीं अपने बचाव में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का कहना है कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को अन्य ऐप स्टोर इस्तेमाल करने की पूरी आजादी देता है।

काला सागर में सुरक्षा पर रूस-यूक्रेन युद्ध का असर

सोफ्रिया, एजेंसी। बुल्गारिया की राष्ट्रपति इलियाना योतवा ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति में ‘महत्वपूर्ण गिरावट’ आई है। बुल्गारिया के तट के पास ड्रोने हमलों में दो वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। हमलों में टोगो-ध्वज वाला जहाज अफ्फा वॉनन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर डूब गया, जबकि पलाऊ-ध्वज वाला एबल आग लगने के बाद क्षतिग्रस्त हुआ। पहले के सभी 18 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया, लेकिन अफ्फा वॉनन के चालक दल की तलाश बुधवार को रोक दी गई और अधिकारी जीवित व्यक्ति या शव का पता नहीं चल सका।

रूसी लैब में कर्मचारी की मौत पर डब्ल्यूएचओ ने मांगी जानकारी, प्लेग की आशंका, खतरे का अभी पता नहीं

जिनेवा, एजेंसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस ऐडेरगनोम गैबरयेसस ने रूस के एक प्लेग संबंधी लैब में एक कर्मचारी की मौत पर सरकार से और जानकारी मांगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास अभी तक घटना की पूरी जानकारी नहीं है, जिससे वह खतरे का आकलन करने में असमर्थ है. एक मीडिया ब्रीफिंग में बुधवार को टेड्रोस ने कहा कि शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में इरकुत्स्क एंटीप्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में लैब में अचानक से हुए न्यूमोनिक प्लेग के संदिग्ध मामले का सुझाव दिया गया था. टेड्रोस ने कहा, 'पिछले शुक्रवार 2 अक्टूबर को रशियन फेडरेशन में इरकुत्स्क एंटीप्लेग

रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक लैब वर्कर में न्यूमोनिक प्लेग के संदिग्ध मामले की पहली मीडिया रिपोर्ट सामने आई। उन्होंने आगे कहा, 'लैब वर्कर की गंभीर निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद मौत हो गई. शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में लैब में अचानक से हुए न्यूमोनिक प्लेग के संदिग्ध मामले का सुझाव दिया गया था.' टेड्रोस ने कहा कि डब्ल्यूएचओ को पता था कि रूसी सरकार ने 2 अक्टूबर को एक मीडिंग की थी, जब उन्हें शक था कि इरकुत्स्क ओब्लास्ट के एक रहने वाले को खतरनाक इन्फेक्शन हो गया है. उन्होंने कहा, 'शनिवार को डब्ल्यूएचओ ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के मुताबिक रूसी



फेडरेशन से और जानकारी मांगी। टेड्रोस के मुताबिक रूस ने मंगलवार को जवाब दिया कि इरकुत्स्क ओब्लास्ट में हाल ही में प्लेग का कोई मामला सामने नहीं आया है, जबकि करीब 200 कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन में रखा गया है. उन्होंने कहा, 'हालांकि वेरिफिकेशन की भी मांग की है, जिसे बिना पता चले निमोनिया होने

टेस्ट्स के बारे में और जानकारी मांगी है. पब्लिक हेल्थ उपायों को क्यों शुरू किया गया, इस बारे में और डिटेल मांगी है, और कॉन्टैक्ट्स की हेल्थ स्टेटस के बारे में डिटेल मांगी है.' डब्ल्यूएचओ ने एक दूसरे कर्मचारी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स की वेरिफिकेशन की भी मांग की है, जिसे बिना पता चले निमोनिया होने

योगी सरकार ने महिलाओं को दिया मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का तोहफा

लखनऊ,, एजेंसी। उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत दे दी है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान होली और दीपावली पर एक-एक मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर भरवाने की योजना जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना पर राज्य सरकार 2,142.78 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कैबिनेट बैठक के बाद खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि योजना के तहत पहला मुफ्त सिलेंडर अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच दीपावली के मौके पर और दूसरा जनवरी से मार्च 2027 के बीच होली पर मिलेगा। इसका लाभ उन्हीं उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा, इनके बैंक खाते आधार से जुड़े होंग और आधार प्रमाणीकरण पूरा होगा। योगी सरकार का कहना है कि इस



योजना से गरीब परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध करने और स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बैठक में जेवर हवाई अड्डे का नाम 'नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा-जेवर' रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी ने इसकी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री योगी ने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख कर कहा कि प्रदेश में 65 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए हैं। करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 2.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल

कनेक्शन मिले हैं, जबकि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.86 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। इनके माध्यम से 9.90 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। योगी सरकार के अनुसार, गंभीर बीमारियों से पीड़ित 1.09 करोड़ लोगों के उपचार पर 18,798 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने रोजगार और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उपलब्धियां गिनाकर कहा कि प्रदेश में 9.50 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और निजी क्षेत्र में 65 लाख नियुक्तियां हुई हैं। उन्होंने बताया कि 10 लाख स्वयं सहायता समूहों से एक करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से गरीब परिवारों, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचा है।

शक के आधार पर किसी को बांग्लादेशी बताकर नहीं निकाल सकती सरकार

बंगाल की शुभेंदु की सरकार पर भड़के जज

कोलकाता, एजेंसी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरुवार को खुली अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार किसी को केवल शक के आधार पर बांग्लादेशी बताकर देश से नहीं निकाल सकती है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की कोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने का पर्याप्त मौका देना चाहिए। यह टिप्पणी मुर्शिदाबाद के एक व्यक्ति की हिरासत और उसे देश से बाहर भेजने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल को कुछ पड़ोसियों के बयानों से पैदा हुए शक के आधार पर 8 अप्रैल से हिरासत में रखा गया था। याचिकाकर्ता की पत्नी ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस



(एफआरआरओ) द्वारा उनके पति को देश से बाहर भेजने और हिरासत में लेने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में पत्नी को हिरासत में नहीं लिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील रबीउल इस्लाम ने सुनवाई के दौरान कहा, मेरे मुवक्किल को दो महीने से ज्यादा समय से हिरासत में

रखा गया है। उन्हें कुछ पड़ोसियों के बयानों से पैदा हुए शक के आधार पर हिरासत में लिया गया। इस पर जस्टिस भट्टाचार्य ने सरकार के वकील से सवाल किया कि उस व्यक्ति को दो महीने तक हिरासत में क्यों रखा गया? उन्होंने यह भी पूछा कि अधिकारियों ने उसकी नागरिकता तय करने के लिए स्पष्ट और योग्य प्रक्रिया का

केंद्र सरकार की नीतियों से कुछ चुनिंदा उद्योगपति समूहों को फायदा : मल्लिकार्जुन खड़गे

नई दिल्ली (एजेंसी) । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आर्थिक नीतियों के जरिए एकाधिकार और दो कंपनियों के दबदबे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से कुछ चुनिंदा उद्योगपति समूहों को फायदा मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पोस्ट कर भाजपा पर आर्थिक उदारीकरण की भावना को कमजोर करने और अपने हितों के लिए आर्थिक आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले इस क्षेत्र में 13 कंपनियां थीं, जबकि अब तीन बड़ी निजी कंपनियों का दबदबा रह गया है। उन्होंने घरेलू विमानन क्षेत्र का जिक्र कर कहा कि पहले सात बड़ी कंपनियां थीं, लेकिन अब प्रमुख बाजार में दो कंपनियों का प्रभाव है। उनके मुताबिक, डिजिटल भुगतान, सीमेंट और भोजन पहुंचाने वाले मोबाइल मंचों सहित कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कम होने की स्थिति दिखाई देती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इन नीतियों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नुकसान हुआ है तथा युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है।

ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार पर फिर दावेदारी: बोले- आठ युद्ध रुकवाए, सम्मान नहीं मिला तो समिति की होगी बदनामी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार पर अपना दावा ठेक दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने दुनिया में आठ युद्ध खत्म कराए हैं और ऐसे काम किए हैं, जो उनसे पहले किसी ने नहीं किए। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर इतने बड़े काम करने के बाद भी उन्हें यह सम्मान नहीं मिलता, तो इससे नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति की साख को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने ये बातें बुधवार दोपहर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को नॉर्वे की नोबेल समिति करने वाली है।

रुकवाने का दावा करता है, तो उसके योगदान को नजरअंदाज करना समिति के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि वह यह बात किसी नागराजगी या तंज के तौर पर नहीं, बल्कि अपने कामों के आधार पर कह रहे हैं।

आठ महीने से जारी युद्ध पर भी ट्रंप की नजर : ट्रंप ने संकेत दिया कि उनकी युद्ध रुकवाने की कोशिशें अभी खत्म नहीं हुई हैं और वह एक और संघर्ष को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनका इशारा अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध की ओर था, जो अब आठवें महीने में पहुंच चुका है। ट्रंप ने इस संभावित पहल को लेकर विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि वह अपने शांति प्रयासों को नोबेल पुरस्कार के दावे का अहम आधार बना रहे हैं। ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 में मिले नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र करते हुए कहा कि वह खुद इस सम्मान के ज्यादा हकदार हैं। उन्होंने ओबामा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि वह पुरस्कार किस वजह से मिला था। ट्रंप के मुताबिक, ओबामा को राष्ट्रपति चुने जाने के तुरंत बाद ही यह सम्मान दे दिया गया था।



पणजी (एजेंसी)। अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्हें अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया है। डॉक्टरों के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया जाता है, तो इसे मेडिको-लीगल केस माना जाता है और पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होता है। डॉक्टरों ने शुरुआती तौर पर नाना पाटेकर की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई है। बताया जा रहा है कि उन्हें पहले से दिल से जुड़ी बीमारियां थीं और वे नियमित दवाइयां ले रहे थे। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और परिवार के सदस्यों सहित मामले से जुड़े अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जांच में अगर मौत प्राकृतिक कारणों से पाई जाती है, तो मामला बंद कर दिया जाएगा। वहीं, अगर किसी तरह के गलत होने का कोई भी संकेत मिलता है, तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बता दें कि नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पुणे के डोंजे गांव में स्थित उनके फार्माहाउस नानावी वाड़ी के आसपास किया गया, जहां उनकी पत्नी नीलकांति पाटेकर और बेटे मल्हार पाटेकर ने उन्हें मुखाग्नि दी।